

संपादकीय

अघोषित कटौती का अंधेरा और डगमगाता भरोसा

ऊर्जा प्रदेश का दावा और जमीन पर अंधेरा क्यों

मध्यप्रदेश को कभी ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सरप्लस राज्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वही राज्य अघोषित बिजली कटौती के संकट से जूझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संकट ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। बिजली कंपनियां और सरकार भले ही चौबीस घंटे आपूर्ति का दावा करें, लेकिन धरातल पर स्थिति चिंताजनक है। लोड शेडिंग के नाम पर सात से आठ घंटे तक बिजली गायब रहती है। कई जिलों में रात के समय भी आपूर्ति बाधित हो रही है। मांग और आपूर्ति में लगभग 1400 मेगावाट का अंतर इस संकट की प्रमुख वजह बताया जा रहा है। किसानों में कटौती को लेकर गहरा आक्रोश है और कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। यह केवल बिजली का संकट नहीं, बल्कि शासन की दूरदर्शिता पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न है। प्रदेश के कई जिलों से किसानों की परेशानी की खबरें आ रही हैं। दिन में पांच से छह घंटे और रात में दो घंटे की कटौती ने ग्रामीण जीवन को संकट में डाल दिया है। भारतीय किसान संघ सहित कई किसान संगठन सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि आपूर्ति नहीं सुधरी तो किसान सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। जब अन्नदाता ही अंधेरे में रहेगा, तो व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा?

बिजली कंपनियों और सरकार का तर्क है कि मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं हो रही और इस वर्ष बांधों में पर्याप्त पानी नहीं है। सवाल यह है कि क्या कम वर्षा और जलाशयों में घटते जलस्तर का अनुमान पहले नहीं लगाया जा सकता था? यदि संकट की आशंका थी, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने के लिए दीर्घकालिक अनुबंध और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को सक्रिय करने की दिशा में क्या तैयारी की गई? प्रदेश के अधिकांश जिलों में मेटेरेन और लोड शेडिंग के नाम पर सात से आठ घंटे तक बिजली बंद रहना प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है। यह कैसा मेटेरेन है, जिसकी मार फसल के नाजुक समय पर किसानों को झेलनी पड़ रही है? यह समय रबी की बोवनी और सिंचाई की तैयारी का है। पानी की कमी के बीच बिजली नहीं मिलने से सिंचाई पंप ठप पड़े हैं। रतलाम जिले में करीब बीस साल बाद ऐसे हालात बने हैं। सामान्यतः वहां 35 इंच वर्षा होती है, लेकिन इस बार केवल 23 इंच बारिश हुई। घोलावद बांध केवल 45 प्रतिशत भर पाया, जिससे सिंचाई पर रोक लगा दी गई है। बड़वानी, बैतूल, भिंड, सतना, नीमच, हरदा और सीहोर सहित कई जिलों में भी किसान परेशान हैं। बिजली और पानी की कमी का यह दोहरा संकट फसलों को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। जल संकट और बिजली संकट एक-दूसरे से जुड़े हैं। पानी की कमी से बिजली उत्पादन प्रभावित होता है और बिजली के अभाव में खेतों तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। यह दुष्प्रक्र प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं। सरकार को ऊर्जा नीति की समीक्षा करते हुए सौर ऊर्जा, वैकल्पिक स्रोतों और किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने की योजनाओं पर तेजी से काम करना चाहिए।

बिजली कटौती केवल तकनीकी समस्या नहीं है। यह किसानों की आजीविका, छात्रों की पढ़ाई, छोटे उद्योगों और आम आदमी के भरोसे से जुड़ा प्रश्न है। सरकार को किसानों के लिए निर्धारित समय पर निम्बांध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ जल प्रबंधन और बिजली खरीद की व्यवस्था भी दुरुस्त करनी होगी। समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो अघोषित कटौती जनआक्रोश में बदल सकती है। ऊर्जा प्रदेश को अंधेरे से निकालना जरूरी है, क्योंकि अंधेरा केवल घरों में नहीं होता, भरोसे में भी होता है और भरोसे का अधेरा सबसे खतरनाक होता है।

आजकल

नई पीढ़ी से नए भविष्य का आह्वान पीएम की अपेक्षा और युवाओं का उत्साह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में एक स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में छात्रों से जो बात कही, वह केवल भाषण नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए संदेश था। उन्होंने जेन जी देश में उपलब्ध असमी अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि विकसित भारत के लिए युवा जो नए विचार और समाधान तैयार करेंगे, वे न केवल देश, बल्कि दुनिया का भविष्य भी तय करेंगे। इस संदेश में युवाओं से जुड़ी बड़ी अपेक्षा और एक दृगामी दृष्टि छिपी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है और युवाओं में भविष्य का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने तमिल भाषा और संस्कृति की सराहना करते हुए प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल को जीवन का महान मार्गदर्शक बताया। उन्होंने यह भी याद किया कि इसकी प्रति रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट की थी। युवाओं से तमिल संस्कृति को साथ लेकर चलने और मित्रों के साथ अपनी परंपराएं साझा करने की अपील भी की। उनका संदेश स्पष्ट था कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान से राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है।

जेन जी यानी वर्ष 2000 के बाद जन्मी पीढ़ी इंटरनेट और तकनीक के साथ बड़ी हुई है। यह केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाली पीढ़ी भी है। भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही दिशा और अवसर मिले तो विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है, अन्यथा यही शक्ति चुनौती बन सकती है। स्टार्टअप इंडिया, अटल टिंकरिंग लेब्स और स्मार्ट इंडिया हेक्थॉन जैसी पहल युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास हैं। लेकिन केवल आह्वान से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। युवाओं को प्रयोग करने की स्वतंत्रता, असफलताओं से सीखने का अवसर और नौकरशाही की बाधाओं से मुक्ति भी चाहिए। उनकी समस्याओं को सुनना और संवाद बनाए रखना जरूरी है। जेन जी भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि इस शक्ति को सही दिशा और पर्याप्त अवसर मिले, तो भारत न केवल विकसित राष्ट्र बनेगा, बल्कि दुनिया को नई राह दिखाने में भी सक्षम होगा।

मध्य

प्रदेश को अब तक धान और गेहूं के कटोरे के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब सरकार ने फसल का नक्शा बदलने की तैयारी की है। 2,442 करोड़ रुपये का मेगा प्लान तैयार हुआ है, जिसके तहत 55 नई दाल मिलें स्थापित की जाएंगी। यह योजना केवल मिल लगाने की नहीं, बल्कि फसल पैटर्न बदलने की है। अब किसानों को धान और गेहूं के साथ-साथ तुअर, उड़द, मसूर और चना जैसी दालों को और ले जाया जाएगा। इसका उद्देश्य दोहरा है, एक तरफ किसानों को अधिक लाभ देना और दूसरी तरफ देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, लेकिन फिर भी उसे बड़ी मात्रा में दालों का आयात करना पड़ता है। यह विरोधाभास है कि हम सबसे ज्यादा दालें उगाते हैं, फिर भी आयात पर निर्भर हैं। इसका कारण हमारी मांग का अधिक होना और उत्पादकता का अपेक्षाकृत कम होना है। दाल केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रोटीन का सस्ता स्रोत है। जब देश में कुपोषण

भारत

की सुरक्षा का इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन एक सच हमेशा से चिंता का विषय रहा है कि हमारे कुछ हिस्से भौगोलिक रूप से इतने नाजुक हैं कि दुश्मन की नजर हमेशा उन पर टिकी रहती है। उन्हीं में से एक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन नेक कहा जाता है। यह लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा एक भूभाग है, जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ता है। यदि यह संपर्क मार्ग किसी कारण से बाधित हो जाए, तो चार करोड़ से ज्यादा भारतीयों का शेष देश से संपर्क प्रभावित हो सकता है। इस संवेदनशीलता को चीन भी समझता है। इसी कारण जून 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान इस क्षेत्र की सामरिक अहमियत फिर चर्चा में आई।

उस विवाद ने भारत को यह समझने का अवसर दिया कि केवल सीमा पर जवान तैनात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जवानों तक पहुंचने के रास्ते भी सुरक्षित होने चाहिए। तभी से केंद्र सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सिक्किम क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम तेज किया है। आने वाले वर्षों में इस कॉरिडोर को अधिक सुरक्षित और सक्षम सैन्य मार्ग बनाने की तैयारी है। यह केवल सड़क निर्माण की परियोजना नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और सामरिक तैयारियों को मजबूत करने का प्रयास है।

अभी कठिन पहाड़ी रास्तों और सीमित सड़क नेटवर्क के कारण भारी तोपों और सैन्य दस्तों को सीमा तक पहुंचाने में लंबा समय लग सकता है। युद्ध जैसे हालात में यह देरी गंभीर चुनौती बन सकती है। इसी खामी को दूर करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के 2029

मास्टर प्लान के खिलाफ क्यों उठ रही है आवाज

भोपाल का दिल पुराने शहर में धड़कता है, नक्शे में नहीं

भोपाल

शहर में एक ही चर्चा तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि इस शहर को मुंबई बनाने की जिद छोड़ दीजिए। पिछले 13 दिनों में 810 से ज्यादा आपत्तियां आना इस बात का सबूत है कि शहर के लोग अपने शहर को लेकर कितने संवेदनशील हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा आपत्तियां पुराने शहर से आई हैं। लोगों की मांग सीधी है, पुराने भोपाल को हेरिटेज शहर के रूप में बचाया जाए, उसे तोड़कर ऊंची इमारतों का जंगल न बनाया जाए।

सरकार कह रही है कि यह विकास का प्लान है, जनता कह रही है कि यह पहचान मिटाने का प्लान है। यहीं से टकराव शुरू होता है। भोपाल की पहचान क्या है? बड़ी झील, छोटी झील, वन विहार, भारत भवन, पुरानी गलियां और धीमी रफ्तार वाली जिंदगी। मुंबई की पहचान क्या है? लोकल ट्रेन, ऊंची इमारतें, भागदौड़ और समंदर। दोनों शहरों की आत्मा बिल्कुल अलग है। फिर एक ही तरह का विकास मॉडल दोनों पर कैसे लागू हो सकता है?

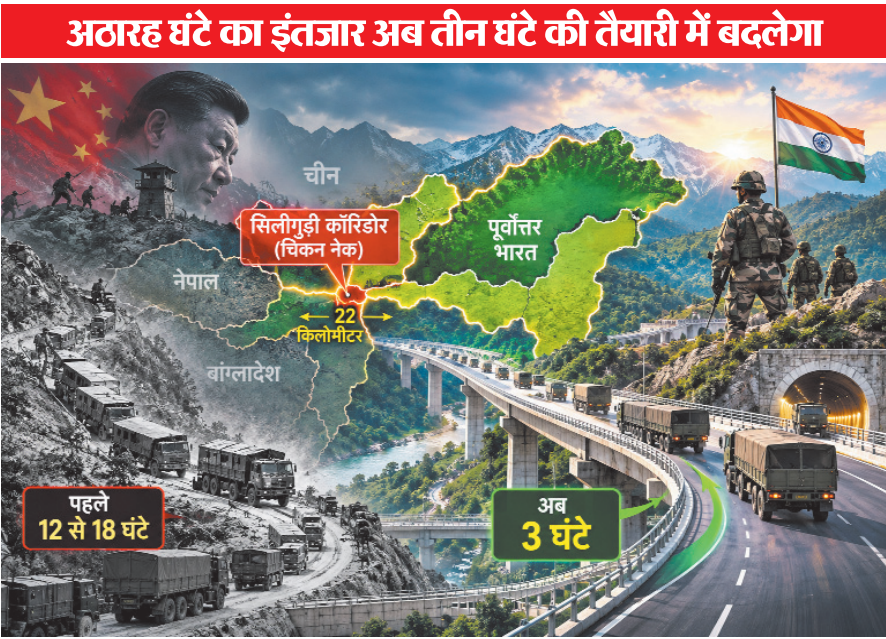
भोपाल के लोगों का डर जायज़ है। मास्टर प्लान में एफएआर बढ़ाने, ऊंची इमारतों को मंजूरी देने और सड़कों को चौड़ा करने की बातें हैं। सड़क चौड़ी होगी तो पुराने शहर की दुकानें टूटंगी, पेड़ कटेंगे और जो पुराने हवेलियां बची हैं, वे भी नक्शे से गायब हो जाएंगी। जब चौक की तांबा-पीतल की दुकानें और इब्राहिमपुरा की गलियां ही नहीं रहेंगी, तो भोपाल में भोपाल जैसा क्या बचेगा?

तेरह दिनों में 810 लोगों का आपत्तियां दर्ज कराना कोई औपचारिकता नहीं है। यह जनमत है। लोग अपना काम छोड़कर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तर जा रहे हैं और लिखित में अपनी बात रख रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें लग रहा है कि यह प्लान उनके बिना बनाया गया है। लोगों ने साफ लिखा है कि पुराने शहर को हेरिटेज जोन घोषित किया जाए, वहां नई बहुमंजिला इमारतों पर रोक लगे और मूल स्वरूप को संरक्षित किया जाए। नए भोपाल में नए प्रयोग किए जाएं, लेकिन पुराने भोपाल को छेड़ा न जाए। यह मांग भावनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक है। दुनिया भर में आज वही शहर पर्यटन के नक्शे पर हैं, जिन्होंने अपनी पुरानी विरासत बचाई है। जयपुर, वाराणसी और पुडुचेरी इसके उदाहरण हैं।

व्यापारी भी इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं। दस मार्केट व्यापारी संघ के महासचिव ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि भोपाल को व्यवस्थित किया जाए, लेकिन उसकी पहचान न मिटाई जाए। व्यापारियों की चिंता वाजिब है। यदि बाजारों को तोड़कर नया बनाया गया तो छोटे दुकानदार कहां जाएंगे? बड़े मॉल में उनकी जगह नहीं है। पुराने बाजारों की अर्थव्यवस्था पैदल चलने वाले ग्राहकों पर

नईदुनिया

चिकन नेक अब कमजोरी नहीं, भारत की मजबूत ढाल



तक पूरा होने पर सैन्य आवाजाही का समय 12 से 18 घंटे से घटकर तीन घंटे रह जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, इस लक्ष्य की वास्तविक उपलब्धि परियोजनाओं के पूरा होने और परिचालन संबंधी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

यह समय की वचत केवल घड़ों की सुइयों का खेल नहीं है, बल्कि रणनीतिक क्षमता में बदलाव का संकेत है। तेज आवाजाही से भारत को संभावित चुनौती का जवाब देने में मदद मिलेगी। सेना की

तैयारी बेहतर होगी और आपात स्थिति में संसाधनों की त्वरित तैनाती संभव हो सकेगी।

एक साथ कई परियोजनाओं पर काम करना बताता है कि सरकार संपर्क मार्गों को अधिक मजबूत बनाना चाहती है। इनमें नई रेल लाइनें, दोहरी लेन वाली सड़कें, सुरंगें और वैकल्पिक मार्ग शामिल हैं। उद्देश्य यही है कि एक रास्ता बाधित होने पर दूसरे मार्ग से आवाजाही जारी रखी जा सके। यह व्यवस्था सैन्य तैयारियों के साथ-साथ आपदा और

मौतों का शॉर्टकट रास्ता बना हार्ट अटैक

अब टीबी नहीं, दिल चुपचाप जान ले रहा है ...

पहले टीबी, कैंसर, एड्स सहित कुछ अन्य गंभीर बीमारियों के कारण पूरे विश्व में सर्वाधिक मौतें होती थीं, लेकिन कोविड के बाद पिछले दो-तीन वर्षों में हार्ट अटैक भी मौतों की बड़ी वजह बनता जा रहा है। अनियमित दिनचर्या, अनियंत्रित खानपान और नींद पूरी न होने के कारण बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, अब संक्रामक

रोगों के बजाय गैर-संक्रामक रोग मौतों के सबसे बड़े कारण बन गए हैं और इनमें भी दिल की बीमारी सबसे ऊपर है। यह बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली के पूरी तरह बदल जाने का प्रमाण है। कोविड ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया है, कोविड से पहले और कोविड के बाद। कोविड से पहले टीबी, दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियां गरीब देशों में मौतों की बड़ी वजह थीं। कोविड के बाद हृदय संबंधी समस्याओं को लेकर भी चिंता बढ़ी है। डॉक्टरों के अनुसार, कोविड के दौरान खून के थक्के जमने की प्रवृत्ति बढ़ सकती थी, जो कुछ मरीजों में हृदय संबंधी जटिलताओं का कारण बनी। यही अजह है कि पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के अचानक गिरने और मौत की खबरें भी चिंता बढ़ा रही हैं। हालांकि, इन घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं।

आज की दिनचर्या का कोई निश्चित समय नहीं रहा। सुबह उठने, रात को सोने और खाने का समय तय नहीं है। बच्चा सुबह स्कूल के लिए भाग रहा है, युवा लैपटॉप पर रातभर काम कर रहा है और महिलाएं घर तथा दफ्तर की जिम्मेदारियां संभालते हुए खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं। इस अनियमितता ने हमारी जैविक बड़ी को प्रभावित किया है। नींद की कमी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकते हैं।

पहले घर में दाल, रोटी और सब्जी बनती थी, अब पैकेटबंद और तले-भुने खाद्य पदार्थों का चलन बढ़ रहा है। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक बच्चों तथा युवाओं की आदत बनते जा रहे हैं। अधिक नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा वाला भोजन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। सिगरेट, शराब और तंबाकू भी हृदय रोगों का खतरा बढ़ाते हैं। शारीरिक मेहनत कम होने के कारण हार्ट अटैक अब केवल शहरों तक सीमित समस्या नहीं रह गया

आपातकालीन परिस्थितियों में भी उपयोगी साबित हो सकती है।

इस बुनियादी ढांचे का मकसद केवल सैन्य नहीं है। पूर्वोत्तर की करोड़ों आबादी का शेष भारत से संपर्क बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रास्ते सुरक्षित और सुगम होंगे, तभी व्यापार, शिक्षा और विकास को गति मिलेगी। व्यापारी अपना माल आसानी से भेज सकेंगे, विद्यार्थी आवागमन कर सकेंगे और क्षेत्र का देश के बाकी हिस्सों से जुड़ाव मजबूत होगा। इसलिए ये मार्ग केवल सैन्य वाहनों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के भरोसे के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

2017 के डोकलाम विवाद से मिली सीख अब भारत की सीमा संबंधी रणनीति में बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित करती है। सीमा पर सुरक्षा केवल जवानों और हथियारों से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि मजबूत सड़कों, रेल संपर्क और वैकल्पिक मार्गों से भी होती है। यदि रास्ते ही उपलब्ध नहीं होंगे, तो आधुनिक हथियारों को सही समय पर सही जगह पहुंचाना मुश्किल होगा।

भारत की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्माण कार्य समय पर पूरे हों और उनका रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए। चिकन नेक की संवेदनशीलता को देखते हुए संपर्क मार्गों का मजबूत होना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ पूर्वोत्तर के विकास के लिए भी जरूरी है। अठारह घंटे से तीन घंटे तक पहुंचने का लक्ष्य कितना सफल होता है, यह समय बताएगा, लेकिन स्पष्ट है कि मजबूत बुनियादी ढांचा ही संकट के समय भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)



है। नींद केवल थकान मिटाने का माध्यम नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। लगातार कम सोने से रक्तचाप और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। देर रात तक मोबाइल चलाना, तनाव और अनियमित दिनचर्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।

हार्ट अटैक को बुजुर्गों की बीमारी मानना भी गलत है। अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, तनाव और अन्य जोखिम कारकों के कारण युवाओं में भी हृदय रोग सामने आ रहे हैं। महिलाओं में भी हृदय संबंधी समस्याओं को लेकर जागरूकता जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का अनुपात बहुत अधिक है। इनमें हृदय रोग प्रमुख है। इसका स्रोत यह है कि खानपान, दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

हार्ट अटैक से बचाव के लिए समय पर सोना और जागना, नियमित व्यायाम करना, संतुलित भोजन लेना, तनाव कम करना और तंबाकू से दूर रहना जरूरी है। रक्तचाप, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच भी करानी चाहिए। सोने में देर, सांथ लेने में परेशानी या अचानक पसीना आने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

हार्ट अटैक कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे केवल भाग्य के भरोसे छोड़ा जाए। हमारी जीवनशैली इसके जोखिम को प्रभावित करती है। सुविधा के नाम पर हमने शरीर की मेहनत कम कर दी है और स्वाद के नाम पर पोषण की अनदेखी की है। अब समय है कि हम अपनी आदतों में सुधार करें, समय पर खाएं, पर्याप्त नींद लें, पैदल चलें और तनाव कम करें। दिल को स्वस्थ रखने के लिए जीवनशैली में बदलाव जरूरी है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

मध्य

प्रदेश को अब तक धान और गेहूं के कटोरे के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब सरकार ने फसल का नक्शा बदलने की तैयारी की है। 2,442 करोड़ रुपये का मेगा प्लान तैयार हुआ है, जिसके तहत 55 नई दाल मिलें स्थापित की जाएंगी। यह योजना केवल मिल लगाने की नहीं, बल्कि फसल पैटर्न बदलने की है। अब किसानों को धान और गेहूं के साथ-साथ तुअर, उड़द, मसूर और चना जैसी दालों को और ले जाया जाएगा। इसका उद्देश्य दोहरा है, एक तरफ किसानों को अधिक लाभ देना और दूसरी तरफ देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, लेकिन फिर भी उसे बड़ी मात्रा में दालों का आयात करना पड़ता है। यह विरोधाभास है कि हम सबसे ज्यादा दालें उगाते हैं, फिर भी आयात पर निर्भर हैं। इसका कारण हमारी मांग का अधिक होना और उत्पादकता का अपेक्षाकृत कम होना है। दाल केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रोटीन का सस्ता स्रोत है। जब देश में कुपोषण

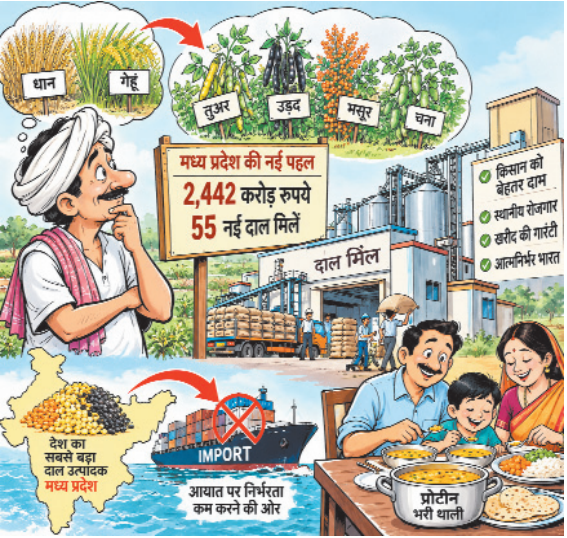
थाली का प्रोटीन, खेत की ताकत और देश की आत्मनिर्भरता

की बात होती है, तो दाल गरीब की थाली में प्रोटीन पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। इसलिए दालों का उत्पादन बढ़ाना केवल कृषि का लक्ष्य नहीं, बल्कि पोषण सुरक्षा का भी लक्ष्य है।

मध्य प्रदेश इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में दालों का उत्पादन 52 लाख टन से अधिक है। मालवा और बुंदेलखंड की जमीन चना और मसूर के लिए जानी जाती है, जबकि विन्ध्य क्षेत्र तुअर के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। प्रदेश की मिट्टी और जलवायु दलहन फसलों के अनुकूल हैं। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की व्यापक संभावनाएं हैं।

सरकार ने इस मिशन के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, जिसमें से 2,442 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की

गई है। इसके तहत 55 नई दाल मिलें स्थापित की जाएंगी। ये मिलें केवल दाल प्रसंस्करण का काम नहीं करेंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा करेंगी। अभी किसान दाल उगाता है, लेकिन उसे बेचने के लिए दूर जाना पड़ता है। व्यापारी कम दाम पर खरीदकर उसे बड़ी मिलों तक पहुंचाते हैं। यदि गांव के पास ही मिल होगी, तो किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पीएम आशा के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना को भी जोड़ा है, ताकि किसानों को



न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे क्या बोएं। यदि धान और

तुअर, उड़द और मसूर की खरीद का भरोसा होगा, तभी वे धान और गेहूं के विकल्पों पर गंभीरता से विचार करेंगे

फसल पैटर्न बदलना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि धान और गेहूं की खेती में पानी की अधिक जरूरत होती है। इसके मुकाबले चना, मसूर, अरहर और उड़द जैसी फसलें अपेक्षाकृत कम पानी में उगाई जा सकती हैं। दलहन मिशन के तहत पांच वर्षों में 442 करोड़ रुपये की कार्ययोजना का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी है। दालों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में उपलब्ध कराने में मदद करता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और अगली फसल को भी लाभ मिल सकता है।

दालों के उत्पादन में अच्छे बीजों की उपलब्धता और बाजार की अनिश्चितता बड़ी चुनौतियां हैं। कई बार किसान पुराने बीज बोते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। सरकार को जलवायु के अनुकूल उन्नत बीज समय